



## भारी बारिश से फिर पानी-पानी हो गए एमपी और राजस्थान

एमपीके 21 जिलोंमें बिंगड़े हालात, राजस्थानमें डैम और रफले

नोएडा स्टेडियम में पानी भरा, न्यूजीलैंड-अफगानिस्तान टेस्ट नहीं हुआ

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। विदिशा,



रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना और अशोकनगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिंतंतर के सबसे शून्य स्टेटमें पूरा मध्यप्रदेश तब्तर हो रहा

एक दिन शादी नहीं चली और देने पड़े 50 लाख

● देने उपीड़िन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी हिंता

नई दिल्ली (एजेंसी)। देने उपीड़िन और घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने वाला सेक्यूरिटी 498ए देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाला कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह बत कहा। जरिस बीआर गढ़, जरिस प्रशासन कुमार मिश्र और जरिस के विश्वासनाथन की बीच नए एक वैयाहिक मामले में विवाद की सुनवाई करते हुए यह बत कहा है। जरिस गवर्नर ने उजारा भी पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आजादी पानी ही सरस अच्छी वीज है। अपनी इस टिप्पणी को विस्तार देते हुए

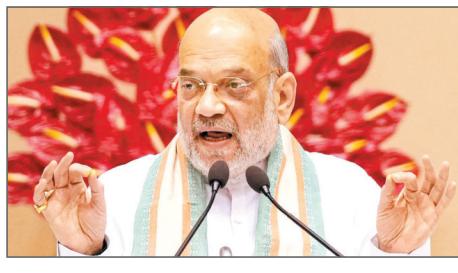


जरिस गवर्नर ने एक केस को भी याद किया। उन्होंने कहा कि एक मामला ऐसा भी आया था, जो पति एक दिन भी पत्नी के साथ नहीं रहा। लेकिन जब वे अलग हुए तो 50 लाख रुपये की रकम उस पत्नी को देनी पड़ी। जरिस गवर्नर ने कहा, मैंने नागरुक में एक केस देखा था। उस मामले में युवक अमेरिका जाकर बस गया। उसकी शादी एक दिन भी नहीं रही। लेकिन पत्नी को केस चलने पर 50 लाख रुपये की रकम देनी पड़ गई। मैं तो खुलकर कहता रहा हूं कि घरेलू हिंसा और देने उपीड़िन के कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। मेरी बात से शायद आप लोग सहमत होंगे। इस कानून के आलोचकों का कहना रहा है कि अक्सर महिला के परिवार वाले इस कानून का बेजा इस्तेमाल करते हैं। रिस्ते खराब होने पर पति और उसके परिवार वालों को फँसाने की धमकी दी जाती है।

## राहुल ने आरक्षण पर कांग्रेस का असली चेहरा दिखा दिया

कांग्रेस नेता के यूएस से आए व्यायाम पर खूब बरसे अमित शाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए राहुल गांधी के एक बयान ने भारत की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने कोटा पर एक स्वाल के जवाब में कहा था कि अपनी आरक्षण को खम्ब करने का सही समय नहीं आया है। उनके जवाब को लेकर विवाद पैदा हो गया है और अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने उन पर तीक्ष्णा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा, आरक्षण समाप्त करने की बात करके राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विवारी था। राहुल का व्यायाम क्षेत्रवाद, धर्म और भाषा के ओर पर दराया करने की कांग्रेस की धौरानी ने उनका जागरूक होने की विवादाता है। राहुल गांधी ने व्यायाम का आरक्षण विवाद पर एक बार फिर से देश के समान लाइखा है।



जॉन कश्मीर में जेकेपनसी के देशविरोधी और अरक्षण विवादी एजेंडे का समर्थन करना हो, या फिर विदेशी मंत्रों पर भारत की बातें करनी हो, राहुल गांधी

दैनिक संस्कार उजाला  
न्यूज एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें



संस्कार उजाला समाचार पत्र में रिपोर्टर, व्यूरोचीफ, मार्केटिंग करने वालों लोगों की जरूरत है। तुरंत संपर्क करें।

महेश शर्मा  
प्रबंध संपादक  
मो.नं:- 9811733939

## शिमला में मरिजद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर बवाल

हिंदू संगठनों का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस के बैरिकेट तोड़े, पथराव

पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर फैन चलाई, पथराव में सिपाही धायल



तो नगर निगम में शिक्षायत की गई थी। अब मरिजद 5 मिलियन है। नागर निगम 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का अद्वेष दे चुका है। ताजा विवाद 31 अगस्त से शुरू हुआ, जब 2 गुटों के बीच मारपीछा हुआ। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मरिजद का अवैध निर्माण गिराने की चाही दी। उनके अन्यम कश्यप ने संजौली में धारा 163 लागू की है। इसके तहत सुबह 7 बजे से रात 11.59 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों को इकट्ठे होने वा व्यथियार लेकर चलाने की इजाजत नहीं होती। पुलिस ने मंगलवार रात को संजौली में शिक्षायत बनाए रखने के लिए फलाने मार्च भी निकाला। साकरी और प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, बाजार पूरी तरह से खुले रहे। किसी भी व्यक्ति को धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। लाउडपायर के इस्तेमाल पर भी प्रतिक्रिया लाया गया है। संजौली में मरिजद का निर्माण 1947 से पहले हुआ था। तब मरिजद को बिलिंडग कही थी।

2010 में इसकी पक्की इमारत बननी शुरू हुई

जय श्रीराम के नारे लगाए। उन्होंने पुलिस के बैरिकेट तोड़ा दिया। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया और बाटर कैनन चलाई गई। पथरावाजी और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और सिपाही धायल हुआ है।

संजौली में मरिजद का निर्माण 1947 से पहले हुआ था। तब मरिजद को बिलिंडग कही थी।

## कपर्यू, इंटरनेट बैन और 2000 जवान फिर पहुंचे

मणिपुर में नहीं संभल रहे हालात, तनावपूर्ण माहौल



नई दिल्ली (एजेंसी)। मणिपुर में एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बीते कुछ दिनों में हुई झड़पों के चलते हालात ऐसे हैं कि तीन जिलों में कम्प्यूल लगाना पड़ा है। और इंटरनेट भी सम्पूर्ण किया गया है। अमित शाह को पत्र भी लिखा है और मांग की है कि हिंसा की विवादाता हो। उन्होंने कहा कि इस उपरान्त भी लोगों के बीच अफवाह फैलने से रोका जा सके। जांच की जाए। उन्होंने कहा कि इस उपरान्त में डास्टी अफवाह और बाहरी तत्व की भी योगदान है। इसके अलावा उन्होंने इसके पीछे विदेशी साजिश को भी बताया है। किलहाल नए सिरे से फैली हिंसा ने मणिपुर में एक बार फिर से उबल लैदा कर दिया है।

## भारत विरोधी सांसद से मिलकर बुरे फंसे राहुल गांधी

भाजपा हमलावर, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा कहा था



मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ इल्हान उमर की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसके बाद सत्तारूप भाजपा कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। पात्रों के बीच विवाद के सासद ए. बियोल अकाइजाम ने अमित शाह को पत्र भी लिखा है और मांग की है कि हिंसा की विवादाता हो। उन्होंने कहा कि इस उपरान्त में डास्टी अफवाह और बाहरी तत्व की भी योगदान है। इसके अलावा उन्होंने इसके पीछे विदेशी साजिश को भी बताया है। किलहाल नए सिरे से फैली हिंसा ने मणिपुर में एक बार फिर से उबल लैदा कर दिया है।

## कर्नाटक में कुछ बड़ा होने के बन रहे आसार

● यूएस में गिले राहुल गांधी और डीके शिवकुमार बढ़ गई अटकलें

बैंगलुरु (एजेंसी)। जीवन मामले को लेकर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमेया ने तेज बदलने की अटकलें जारी हैं। हालांकि, इसे लेकर कांग्रेस की ओर से अधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। शिवकुमार ने एक बार राहुल गांधी की अटकलें जारी की थीं। उन्होंने इसके बाद राहुल गांधी की अपील के बीच ज्ञानवान अटकलें जारी की थीं। उन्होंने इसके बाद राहुल गांधी की अपील के बीच ज्ञानवान अटकलें जारी की थीं। उन्होंने इसके बाद राहुल गांधी की अपील के बीच ज्ञानवान अटकलें जारी की थीं। उन्होंने इसके बाद राहुल गांधी की अपील के बीच ज्ञ

# घुटती सांसों से कम होती औसत आयु की चिन्ता



ललित गर्गी

निश्चित ही वायु  
प्रदूषण से उत्पन्न  
दमघोट माहौल का  
संकट जीवन का  
संकट बनता जा रहा  
है। वायु प्रदूषण का  
ऐसा विकराल जाल  
है जिसमें मनुष्य  
सहित सारे जीव-जंतु  
फँसकर छटपटा रहे  
हैं, जीवन सांसों पर  
छाये संकट से जूँझ  
रहे हैं। यह समस्या  
साल-दर-साल गंभीर  
होती जा रही है।

**ज** वायु प्रदूषण का संकट भारत की राष्ट्रव्यापी समस्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की हाल ही में जारी रिपोर्ट इस चिन्हा को बढ़ाती है कि जिसमें कहा गया कि वायु प्रदूषण के चलते भारत में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आ रही है। जिसमें फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले पी.एम. 2.5 कण की बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक मानकों से कहीं अधिक प्रदूषण भारत में लोगों की औसत आयु तीन से पांच वर्ष एवं दिल्ली में दस से बाहर वर्ष कम कर रहा है। बहरहाल प्रदूषण के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से मुहिम छेड़ने की जरूरत है। अध्ययन कहता है कि देश की एक अब से अधिक आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां प्रदूषण डब्ल्यूएचओ के मानकों से कहीं अधिक है। दरअसल, देश के बड़े शहर आबादी के बोझ से त्रस्त हैं। बढ़ती आबादी के लिये रोजगार बढ़ाने व अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो औद्योगिक इकाइयां लगायी गईं, उनकी भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका रही है। डीजल-पेट्रोल के निजी वाहनों को बढ़ता काफिला, निर्माण कार्यों में लापरवाही, कचरे का निस्तारण न होना और जीवाशम ईंधन ने प्रदूषण बढ़ाया है। यह बढ़ता वायु प्रदूषण हमारी जीवन शैली से उपजे प्रदृष्टण की देन भी है।

यह निराशाजनक खबरों के बीच उत्साहवर्धक खबर यह भी है कि भारत में सूक्ष्म करणों से पैदा होने वाले जानलेवा प्रदूषण में गिरावट आई है। लेकिन अभी जीवन प्रत्याशा घटाने वाले प्रदूषण को लेकर जारी लार्डाइ खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पालिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024' बताती है कि भारत में साल 2021 की तुलना में 2022 के वायु प्रदूषण में 19.3 फीसदी की कमी आई है। हालांकि, यह उपलब्ध मौजूदा हालात में बहुत बड़ी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन यह बात उत्साहवर्धक है कि प्रत्येक भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इक्यावन दिन की वृद्धि हुई है। हालांकि, हम अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन एक विश्वास जगा है कि युद्ध स्तर पर प्रयासों से भयावह प्रदूषण के खिलाफ किसी हद तक जंग जीती भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही सूचकांक-2024 में यह चेताया भी है कि यदि भारत में डब्ल्यूचओ के वार्षिक पीएम 2.5 के संद्रंता मानक के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में करीब साढ़े तीन साल की कमी आने की आशंका पैदा हो सकती है। पीएम 2.5 श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकता है और सांस संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। यह स्वास्थ्य को एक बड़ा खतरा है और वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है।

हालांकि, राजधानी समत कई अन्य राज्यों में मट्रो ट्रॉन शुरू



होने के बाद प्रदूषण में काफी कमी आई है। इस दिशा में हमें दीर्घकालीन नीतियों के बारे में सोचना होगा। हमारी कोशिश हो कि घनी आबादी के बीच चलायी जा रही औद्योगिक इकाइयों को शहरों से दूर स्थापित किया जाए। हमारे उद्यमियों को भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देना चाहिए। नीति-नियंत्राओं को सोचना चाहिए कि प्रदूषण में अप्रत्याशित वृद्धि के बाट दिल्ली आदि महानगरों में चलाये जाने वाले ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप जैसी व्यवस्था को नियमित रूप से लागू करें नहीं किया जा सकता? ताजा कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि बढ़ता प्रदूषण नवजात शिशुओं तथा बच्चों की जीवन प्रत्याशा पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में हमें पराली के निस्तारण, औद्योगिक कचरे के नियमन तथा कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन पर रोक लगाने जैसे फौरी उपाय तुरंत करने चाहिए। ऐसे तमाम प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने की जरूरत है जो हमारे जीवन पर संकट पैदा कर रहे हैं।

अध्ययन कहता है कि भारत के सबसे कम प्रदूषित शहर भी डब्ल्यूएचओ के निर्धारित मानकों से सात गुना अधिक प्रदूषित हैं। हम न भूलें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गिनती लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में होती रही है। दीवाली के बाद जब दिल्ली गहरे प्रदूषण के आगोश में होती है तो कोर्ट से लेकर सरकार तक अति सक्रियता दर्शाते हैं। लेकिन थोड़ी स्थिति सामान्य होने पर

परिणाम वही 'दाक के तीन पात'। कभी पेट्रोल-डीजल के नये मानक तय होते हैं तो कभी जीवाशम इंधन पर रोक लगती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2019 में प्रदूषण कम करने को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम देश के सौ से अधिक शहरों में शुरू किया था। चार साल बाद पता चला कि किसी भी शहर ने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। विकासशील देश पहले ही निर्धारित वायु गुणवत्ता के मानक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहीं डब्ल्यूएचओ ने मानकों को और कठोर बना दिया है। सभी सरकारों व नागरिकों का दायित्व बनता है कि अपने-अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने वाली जीवन शैली अपनाएं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया में सतर लाख मौतें हर साल प्रदूषित वायु के चलते हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के अनुसार हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के वार्षिक स्तर की सुरक्षित सीमा क्रमशः चालीस माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और साठ माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। हालांकि, ये मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों से कहीं ज्यादा हैं। दरअसल, हमारे नीति-नियंता प्रदूषण कम करने के लिये नागरिकों को जागरूक करने में भी विफल रहे हैं। हमारी सुख-सुविधा की लालसा एवं भौतिकतावादी जीवनशैली की चमक ने भी वायु प्रदूषण बढ़ाया है। अब चाहे गाहे-बगाहे होने वाली आतिशबाजी हो, प्रतिबंध के बावजूद

पराली जलाना हो, या फिर सार्वजनिक परिवहन सेवा से परहेज हो, तमाम कारण प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। कल्पना कीजिए बच्चों और दमा, एलर्जी व अन्य सांस के रोगों से जूझने वाले लोगों पर इस प्रदूषण का कितना घातक असर होगा?

रिपोर्ट में उल्लेखित प्रदूषण में आई गिरावट की बजह अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां बतायी गई हैं। हालांकि, हकीकत यह भी है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये चलायी जा रही कई योजनाओं के सकारात्मक परिणामों का भी इसमें योगदान रहा है। खासकर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जिन शहरों को शार्मिल किया गया था, वहां भी पीएम-2.5 संदर्भ में गिरावट देखी गई है। वहीं स्वच्छ ईंधन कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव प्रदूषण नियंत्रण पर नजर आया है। इससे भारत के रिहाइशी इलाकों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है। ऐसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। बहरहाल, हमें वर्ष 2022 के उत्साहजनक परिणामों के सामने आने के बाद व्यापक लक्ष्यों के प्रति उदासीन नहीं होना है। यह एक लंबी लडाई है और इसमें सरकार व समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सरकारों के भरोसे ही लगातार गहराते पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है।

निश्चित ही वायु प्रदूषण से उत्पन्न दमघोटू माहौल का संकट जीवन का संकट बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मुख्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छतपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से ज़म्मा रहे हैं। यह समस्या साल-दर-साल गंभीर होती जा रही है। सरकारें अनेक लुभावने तर्क एवं तथ्य देकर समस्या को कमपर दिखाने की कोशिशें करती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि लोगों का दम घुट रहा है। अगर वे सचमुच इससे पार पाने को लेकर गंभीर हैं, तो वह व्यावहारिक धारातल पर दिखना चाहिए। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूँझ रहे राष्ट्र को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? वास्तव में यह विभिन्न राज्य सरकारों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, जिसने सबको जहरीले वायुपंडल में रहने को विवश किया है। इस विषम एवं ज्वलतं समस्या से मुक्ति के लिये हर राजनीतिक दल एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्राष्ट्रीय-सम्पन्न बनना होगा। प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दोपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण-क्षण अग्नि-परीक्षा देता है। पर हां! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता।

# संपादकीय



नमल राना

**ओ** लम्पियन विनेश फोगाट के कंग्रेस में शामिल होने तथा जुलाना विधानसभा क्षेत्र से अपनी चुनावी पारी की शुरूआत करने के बाद एक बात यह भी स्पष्ट हो गयी है कि कंग्रेस विनेश का इस्तेमाल केवल स्पोर्ट्स स्टार और जाट चेहरे मात्र के रूप में ही नहीं करेगी बल्कि वह इस सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय ओलम्पियन के बहाने भारतीय जनता पार्टी को महिला सुरक्षा के नाम पर देशभर में घेरने का भी प्रयास करेगी। भाजपा ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा देकर तथा इस योजना के प्रचार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देश की जनता को यह सन्देश देने की काँशिश की थी कि भाजपा ही बेटी / महिलाओं की एकमात्र हितैषी पार्टी है तथा भाजपा के राज में ही महिलाओं के हितों की पूरी रक्षा व मान सम्मान संभव है। परन्तु यह भी अजीब संयोग है कि इसी भाजपा के राज में देश के अनेक प्रांतों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकीं जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में एक मिसाल बन गयीं। क्या मणिपुर तो क्या बांगला, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से तो ऐसी रूह कांपने वाली अनेक घटनाएं हो चुकीं जिनकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती।

# महिला सुरक्षा भी होगा चुनावों में बड़ा मुद्दा

महिला उत्पीड़न, बलात्कार व हत्या जैसे घृण्ण अपराधों में यह भी देखा गया है कि ऐसे कई भाजा शासित राज्यों में होने वाली ऐसी सनसनीखेज वारदात में भाजपा की ओर से खामोशी बरती गयी जबकि कि गैर भाजपा शासित राज्य खासकर बंगाल में यदि को घटना घटी तो उसे भाजपा द्वारा इस हद तक उछाला गया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की चर्चा तक छिड़ गयी? जबकि मणिपुर में महिलाओं के साथ जै जुल्म हुये वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ही भी नहीं हुये। परन्तु चूँकि मणिपुर भाजपा शासित राज्य है इसलिये इन घटनाओं के लिये न तो वाहां मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया न ही किसी से त्यापन्त्र माँगा गया? उत्तराञ्चल में भी ऊंचे रसूख रखने वाली भाजपाई नेता के पुत्र बलात्कार, हत्या जैसे मामलों शामिल पाए गये। भाजपा शासित राज्यों में घटी ऐसी अनेक घटनायें सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की मुनाफी पर सवाल खड़ा कर रही हैं। इसी बीच ओलम्पियन विनेश फोगाट का कांग्रेस का दामन थामा भी भाजपा के लिये बड़ा सिर दर्द सवित हो सकता है क्योंकि विनेश फोगाट उन विश्वस्तरीय ओलम्पिक पद विजेता पहलवानों में एक है जिसने उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह द्वारा कुछ महिला पहलवानों के साथ कथित रूप से किये गये दुर्व्यवहार के विरुद्ध मोरो खोलते हुये जंतर मंतर पर धरना दिया था। यह धरना गवर्ष 28 मई 2023 को उस समय और भी सुरुखियों में हुआ था जबकि उस दिन नये संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर बृज भूषण सिंह के विरुद्ध धरनारत इन पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक जंतर मंतर घसीट कर धरना समाप्त करा दिया था। उस दिन देश

के दो चरित्र व चेहरे देखे थे। एक तरफ तो उत्पीड़न शिकार देश का मान सम्मान विश्व में बढ़ने वाली बैंग पुलिस जुल्म का शिकार हो रही थीं उन्हें सड़कों घसीटा जा रहा था। जबकि दीक उसी समय उत्पीड़न का आरोपी बृज भूषण सिंह मुस्कुराता हु नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शब्द बढ़ा रहा था। इन्हीं धरनारत पहलवानों में दिल्ली पुलिस की ज्यादितयों का शिकार एक खिलाड़ी विनेश फोगत थी जो अब कंग्रेस में शामिल होकर प्लेटेश को भाग के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के खाँखेले दावों इसकी हकीकत में अंतर से परिचय कराएगी। महिला सम्मान के सवाल को लेकर एक और 'सेंगोल' करते हुये भाजपा द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी से पूर्व जेलर सुनील सांगवान को टिकटिका दिया गया है। सुनील सांगवान की विशेषता यह है रोहतक की सुनारिया जेल में उनके जेल अधीक्षक कार्यकाल के दौरान रेप व हत्या के दोषी गुरमीत रहीम को 6 बार पैरोल मिली थी। इस पैरोल को दिया गया था। इस सहायता करने में जेलर सुनील सांगवान की विभूमिका थी। राम रहीम को मिली पिछली पैरोल के दौरान ही यह स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। तभी जैसे ही रहीम अपनी पैरोल खत्म कर जेल पहुंचा उसके पांच बाद ही सुनील सांगवान ने जेलर पद से त्याग पत्र फॉर्म जिसे फौरन स्वीकार भी कर लिया गया। उसके अगले ही दिन उन्होंने सार्वजनिक मंच पर आकर भाजपा ज्वाइन की। और दो दिन बाद ही भाजपा की पहली राज्यपाली में ही चरखी दादरी से सुनील सांगवान का नाम भाजपा प्रत्याशी के रूप में समन्वेत आ गया। गोया 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा देने वाली भाजपा में गुरमीत रहीम जैसे रेप और हत्या के दोषी व सजा काट

व्यक्ति को पार्टी टिकट भी दिला सकता है? साथ ही ऐसे अपराधी का 'करम फरमाँ' जेलर चुनाव मैदान में आकर महिला सुरक्षा के विषय में अपने क्या विचार रखेगा? यह सब सवाल ओलम्पियन विनेश फोगाट आगामी चुनाव में केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा से देश भर में पूछेंगे जा रही है। भाजपा स्वयं को उन आरोपों से भी दूर नहीं रख सकती जो उसपर बिल्कुल बाने के सजायाप्ता अपराधियों की रिहाई को लेकर लगे थे। क्योंकि गुजरात की भाजपा सरकार ने तो उन सामूहिक बलात्कारियों व हत्यारों को रिहा कर दिया था परन्तु सर्वोच्च न्यायलय ने गुजरात सरकार के इस फैसले को निरस्त हुये उन्हें पुनः जेल की सलाखों के पीछे धकेला। तब कहाँ चला गया था भाजपा का महिला सुरक्षा का दावा? बेटी बच्चाओं योजना का उस समय ध्यान विद्यार्थी नहीं आया? जब भाजपा सरकार के मंत्री विधायक व कार्यकर्ता करुआ की 8 वर्षीय आसिफा के बलात्कार व उसकी हत्या के आरोपियों के पक्ष में जुलूस निकाल रहे थे। जब उनके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकल कर तिरंगे को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उस समय कहाँ था था भाजपा का नारी न्याय और बेटी बच्चाओं का उद्घोष? ऐसे और अनेक सवाल जो भाजपा में महिला बाल विकास मंत्री रही स्मृति ईरानी नहीं पूछ सकती उस तरह के सवाल अब विपक्षी इडिया गठबंधन की तरफ से विनेश फोगाट यानी एक ऐसी ओलम्पियन देश में घूम घूम कर पूछेंगी जोकि स्वयं नारी शोषण शिकार रही है वह भी कथित रूप से भाजपा के दबंग सांसद के द्वारा? इसलिये विनेश फोगाट का कांग्रेस में आना केवल किसी ओलम्पियन का किसी पार्टी में शामिल होना मात्र नहीं है बल्कि विनेश फोगाट के रूप में महिला सुरक्षा भी वर्तमान में हो रहे व भविष्य में होने

# पैरालंपिक में भारत: सोच में आए बदलाव का नतीजा

है। वैसे भी युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक नायक की जरूरत होती है। पर अब देश ने इन खेलों में ढेर नायक खड़े कर दिए हैं, इसलिए युवा भी अपने अपन्गता का दुख मनाने के बजाय खेलों में हाँ आजमाने को आगे आने लगे हैं। वह दिन भी दूर नहीं जब भारत इन खेलों के टॉप दस देशों में नजर आ सकता है। हम पेरिस पैरालॉपिक खेलों की बात करें तो भारत ने 29 में से 13 पदक एथ्लेटिक्स में हासिल किए हैं। भारत द्वारा जीते सात स्वर्ण पदकों में से चाहे और नौ रजत पदकों में से छह पदक एथ्लेटिक्स आए हैं। भारत ने बैडमिंटन और निशानेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पर तीरंदाजी, जूडो, टेबल टेनिस सहित कई अन्य खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन करने की संभावनाएं हैं। भारतीय प्रदर्शन पर हम नज़द़िलें तो साफ दिखता है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधार आ रहा है। इसके लिए प्रवाण कुमार का ऊँचा कूद में टोक्यो के रजत को स्वर्ण में बदलना, हरविंध की तीरंदाजी कांस्य को स्वर्ण में बदलने के अलावा हाईंजंपर शरद कुमार और निषाद कुमार, शटलर सुहायथिराज, डिस्क्स थ्रोअर योगेश का पदक का रेस बदलने को देखा जा सकता है। पैरालॉपिक खेल पहले विश्व स्तर पर ही बहुत लोकप्रिय नहीं थे और भारत में तो इन खेलों की लोकप्रियता का सवाल ही कहा उठता है? यही बजह है कि भारत शुरूआत में इन खेलों में नियमित तौर पर भाग ही नहीं लेता था। 1984 से जब इन खेलों में भाग लेना नियमित तौर पर शुरू हुआ, तब भी उसके भाग लेने में गंभीरता का एकदम से अभाव दिखता था। यही बजह है कि ज्यादातर खेलों में भाग लेने वालों की संख्या 4-6 ही हुआ करती थी। भारत ने 1984 से लेकर 2012 तक आ

खेलों में सिर्फ सात पदक ही जीते। सही मायने भारत में पैरा एथलीटों को सही दिशा मिलने शुरूआत 2016 के रियो पैरालाइपिक से हुई और इसकारी सहयोग के साथ देश की पैरालाइपिक समिति की बागड़ोर पैरा एथलीटों के हाथों में आने ने 3-भूमिका निर्भाई। 2016 के रियो खेलों में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक 2020 में इस समिति प्रमुख बनीं तो आजकल इन खेलों की समिति के द्वारा स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र जाङ्गरिया अध्यक्ष हैं। अब में यह लोग अच्छे से जानते थे कि इन खिलाड़ियों किस तरह ट्रेनिंग की जरूरत है और उनको किसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसी का परिणाम पर 2020 के टोक्यो पैरालाइपिक और पेरिस खेलों में देश को मिला है। यह सही है कि 2016 में भारत ने स्वर्ण सहित चार ही पदक जीते। पर इन खेलों से भारतीय पैरा एथलीटों में यह भावना बनी कि वह इस स्तर पर सुर्खियां बटोर सकते हैं। यह सही है भारत ने 2020 के टोक्यो पैरालाइपिक के 19 पदकों मुकाबले सात स्वर्ण सहित 29 पदक जीतकर 3-प्रदर्शन को सुधारा है। वह अंक तालिका में भी 2 से 18वें स्थान पर आकर पहली बार टॉप 20 देशों शामिल हुआ है। पर भारतीय क्षमता का पूरा उपर अभी भी नहीं हो सका है। इन खेलों में भारत ने एक स्वर्ण और दो रजत पदक और जीत लिए होते तो वह ईरान से ऊपर रहकर 14वें स्थान पर प्रवास करका था। भारत को टॉप दस देशों में शामिल होने प्रयास करना चाहिए। यह काम बहुत आसान तो नहीं पहुंच गया है। भारत इस मुकाम तक ऐसे इसके लिए पैरालाइपिक समिति ने भारत सरकार के स



मिलकर तमाम प्रयास किए और यह इन सभी का परिणाम है। इस समिति की पूर्व अध्यक्ष दीपा मलिक कहती हैं कि मैंने इन खेलों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। इसके लिए इस खेल के आंकड़ों को इंटरनेट पर पड़वाया। प्रतिभाओं की तलाश के लिए देश में जूनियर और सब जूनियर चैम्पियनशिपों का आयोजन कराया। हम सभी जानते हैं कि पैरा एथलीट किन परिस्थितियों से उभरकर सामने आते हैं, इसलिए सबसे जरूरी मनोदेशा को तैयार करना होता है। आधुनिक खेलों में खिलाड़ी की प्रतिभा के साथ मनोवैज्ञानिक तैयारी का महत्व बहुत बढ़ गया है। भारत को ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन सुधारना हो मानसिक मजबूती पर खासतौर से काम करने की जरूरत है।











